विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ) : (क) और (घ) विद्युत परियोजनाओं को विश्व बैंक सहायता प्रदान करने संबंधी गुजरात सरकार का कोई भी नया प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहां तक केन्द्रीय सहायता का संबंध है, केन्द्रीय सरकार राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए ब्लाक योजना सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार प्रदान करती है विद्यमान क्षमता के समायोजन में सुधार लाने के लिए और मांग में प्रक्षेपित वृद्धि को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार नई क्षमताओं की जांच कर रही है तथा विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागेदारी को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है गुजरात विद्युत बोर्ड अपने ताप विद्युत स्टेशनों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए विद्युत वित्त निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है।

(ग) और (घ) गुजरात की पारेषण और शहरी वितरण उप परियोजना संबंधी स्कीमों के लिए विद्युत वित्त निगम लिमि. के जरिये गुजरात विद्युत बोर्ड के लिए 42.59 मिलि० अमरीकी डालर की विश्व बैंक ऋण सहायता मंजूर की गई है।

(ङ) विद्युत उत्पादन दिन प्रतिदिन भिन्न-भिन्न होता है गुजरात में दिनांक 5.8.1997 को कुल ईष्टतम विद्युत उत्पादन 4146 मे. वा. था।

Consultation with Public for Payment of Compensation

2122. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHIL KUMAR
SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Power Grid Corporation of India has drawn out a set of environmental and social policy, committing itself to public consultation at every stage from identification of affected persons to payment of compensation;

(b) if so, the details of the policy; and

(c) its modus operandi?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) Yes, Sir.

(b) The salient features of the Environmental & Social Policy and Procedure (ESPP) framed by POWERGRID are as under:

(i) People coming in the way of the Right of way (ROW) are consulted and their views and suggestions are incorporated thus allowing for public participation.

(ii) The social impacts of land acquisition are assessed based on socio-economic survey and the compensation packages are designed in consultation with the people.

(iii) The plantations and forests are avoided in line routing so as to keep the environmentally pristine areas and human habitations intact.

(iv) Social and environmental assessment of the projects are carried out to evolve a project specific environmental and social management plan.

(c) Environment Management Cells have been opened at Regional Group Head Quarters of POWERGRID for implementation of ESPP and the same is monitored at the Corporate Centre.